MTs of wheat has been released for exports of wheat from the sources other than Food Corporation of India for the year 1996-97.

बिहार में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु कार्य-योजना

2147. **श्री नागमणि:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेशकों एवं उद्योगपतियों को वहां पर पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की गई है या की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) औद्योगिक विकास मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है।

जुलाई, 1991 में घोषित नयी औद्योगिक नीति के अधीन सामरिक महत्व, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी पन्द्रह उद्योगों को छोड़कर लगभग सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी को भारत सरकार के पास केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) प्रस्तुत करना होता है। स्थापना-स्थल का चयन उद्यमी के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दिया जाता है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा दी गयी आधार भूत तथा अन्य सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

Transparent Disinvestment process

2148. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have evolved a new plan for public sector restructuring to ensure a more transparent disinvestment, which contemplates workers' share holding and mass ownership of PSUs;

(b) if so, the details of the new schemes, its salient features, indicating the elements of scarcity of workers' interest and transparency; and

(c) names of PSU's to be subjected to disinvestment process, under the new scheme in the first phase?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The Government have decided to set up a Disinvestment Commission to facilitate transparent disinvestment of Government share-holding in PSUs. The Commission is to advise the Government on modes of disinvestment which may also contemplate workers' shareholding, mass ownership etc.

(c) Question does not arise as the Commission has not become operational as yet and it is concerned with the first two tranches.

"सेल" के विपणन ढांचे को सुधारने के लिए योजना

2149. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड "सेल" ने अपने सम्पूर्ण विपणन ढांचे में सुधार करने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घाटे में चल रहे "सेल" के एककों को भी अर्थ-क्षम बनाया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) जी, हां। "सेल" की अपने विपणन कार्यों और ढांचों में सुधार हेतु योजनाएं हैं।

(ख) विपणन प्रणाली में सम्मिलित नीतियों, ढांचों और प्राणालियों में परिवर्तन 'सेल' की एक सतत् प्रक्रिया है। विपणन प्रणाली में किए गए कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार है:—

विपणन नीतियों में परिवर्तन: ग्राहकों से व्यापक स्तर पर सम्पर्क बनाए रखना बाजारोन्मुखी उत्पाद मिश्र,